steps that Government is going to take in these matters. Heavy expenditure is involved in entertainment and other things indulged in by high officers abroad. There is undercutting in many matters. We are also some times losing because there is a high competition even in Europe and other places. At the same time, there are subsidised passengers travelling by Air-India.

I would like to know to what extent our officers, even in spite of this expenditure, have turned out business of Air-India. I want a categorical answer to my question om the Minister.

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : फारेन कन्ट्रीज में एअर सर्विसेज में कांपिटीशन बहुत है और व दूसरे देशों में अपने सेल्स प्रमोशन के लिये एन्टरटनमेन्ट, एडवर्टीजमेन्ट और दूसरे तरीकों से बहुत खर्चा करते हैं। उस कांपिटीशन को देखते हुए निश्चित रूप से सेल्स प्रमोशन के लिए खर्च करना पड़ता है। मैं इस सदन की जानकारी के लिए बतला दूं कि निश्चित रूप से हमारा बिजनेस इस साल बढ़ा है। 1976-77 में कुल मिला कर 139 करोड़ की आमदनी हुई थी जिसकी तुलना में इस साल 141 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। इस के अनुपात में हम जो सेल्स प्रमोशन पर खर्चा कर रहे हैं वह तुलात्मक दृष्टि से कम है। सेल्स प्रमोशन के लिये हम जो भी खर्च कर रहे हैं वह हमारी ग्रास रेवन्यु के एक प्रतिशत से भी कम है।

Export of Onions and Potatoes

*532. SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to lay a statement showing :

(a) the names and addresses of the companies and firms who exported onions and potatoes more than 100 tonnes in the last four months:

(b) how much quantity was exported by each firm or company ;

(c) names of the other essential commodities exported in the last four months along-with the amount ; and

(d) do Government propose to change their policy of not exporting essential commodities in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b). Export of potatoes and onions has been stopped. There has been no export of potatoes during the last four months. In order to honour pre-ban commitments and also to meet urgent demands of friendly countries, export of 4279 tonnes of onions was made by the canalising agency (ational Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Ltd.) during August—November 1977.

(c) and (d). Itemwise export data in respect of the last four months has not yet been compiled. The Government policy has been to ban or regulate the exports of items of essential mass consumption in such a manner that there is no adverse effect on domestic availability or prices. Export of such commodities is allowed if there is a surplus over and above the essential domestic requirements.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Before putting my supplementary, I would like to draw your kind attention to part (c) of my question namely the names of the other essential commodities exported in the last four months along with the amount. The reply given by him is that itemwise export data in respect of the last four months has not yet been compiled. At least he should have given the names of other commodities. He has not given.

अब मैं माननीय मंत्री जी को बधायी देना चाहता हूं कि उनकी इस एक्सपोर्ट पर पाबन्दी के बाद आलू और प्याज के दाम इतने कम हो गए हैं कि शायद पिछले एक साल में कभी इतने कम नहीं हुए थे। आज दिल्ली में आलू एक रुपया किलो बिक रहा है और प्याज —मैं आज सुबह का भाव बतला रहा हूं— एक रुपया चालीस पैसा किलो बिक रहा है। (व्यवधान)

MR. SPEAKER : Kindly allow him to put the question. You must patiently hear his question. Kindly come to you question.

श्री कंवर लाल गुप्त : तो आज दिल्ली में आलू एक रुपया किलो और प्याज एक रुपया चालीस पैसा किलो बिक रहा है लेकिन यह उसी नीति के कारण है जिस में आप ने एसेंशियल कमाडिटीज की आइटम्स का एक्सपोर्ट बन्द किया है और इस के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधायी देना चाहता हूं । लेकिन इस के साथ-साथ एक समस्या है । समस्या यह है कि यद्यपि आलू 1 रुपया किलो बिक रहा है, लेकिन ग्रोअर्स को जितना मिलना चाहिये, उतना नहीं मिल रहा है । दूसरी समस्या यह है कि दिल्ली के अन्दर किसी जगह 1 रुपया किलो बिक रहा है , किसी जगह सवा-रुपये किलो बिक रहा है , किसी जगह एक रुपया 40 पैसे किलो बिक रहा है । क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि ग्रोअर्स को ठीक दाम मिले, उस के लिये सरकार क्या कर रही है और मोटे तौर पर एसेन्शल-कमाडिटीज के भाव सब जगह यनिफाइड रहें और ज्यादा फर्क न हो—इस के लिये आप ने क्या किया है ? आप ने पहले कोआपरेटिव्ज की बात कही थी, सस्ते दामों की दुकान की बात कही थी—उसके लिये आप ने क्या किया है ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): The hon. Member has correctly asked about our policy regarding the price to be paid to the growers. I have said on the floor of the House that it was the policy of the government that the grower should get a reasonable and remunerative price and at the sametime we would very much like to take care of the consumers; it is a blending of the two. It is in this context that we were trying to encourage cooperatives of growers on the one hand and consumers associations or cooperatives on the other. The more we establish that link the more it will be possible for things to be taken care of.

श्री कंवर लाल गुप्त : अभी तक सरकार की एड़हाक-पालिसी रही है कि जब ज्यादा पैदावार हो गई तो एक्सपोर्ट खोल दिया, जब कम हो गई तो एक्सपोर्ट बन्द कर दिया । क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इन दोनों चीजों की हमारे देश में पैदावार कितनी है, कितनी रिक्वायरमेन्ट है तथा क्या इस के बारे में आप कोई स्थायी पालिसी तय करेंगे ?

दूसरा प्रश्न—आप ने शुगर पर 20 परसेन्ट एक्साइज ड्यूटी कम की है, लेकिन उस से कन्ज्यूमर को फायदा नहीं हुआ, मिल-मालिकों को फायदा हुआ । ग्रोअर्स को भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आप ने गन्ने के दाम नहीं बढ़ाये । इस के सम्बन्ध में आप को क्या कहना है ?

MR. SPEAKER : Let us not mix up potato with sugar.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : It is one of the essential items.

SHRI MOHAN DHARIA : We are trying to evolve an integrated policy so for as exports of essential articles are concerned .. (*Interruptions*)

SHRI V. ARUNACHALAM : On a point of order. On that day you reserved your ruling on the point raised by our deputy leader.

MR. SPEAKER : There is no point of order during question hour.

SHRI V. ARUNACHALAM : This point was raised that day.

MR. SPEAKER : Before any member gets a stick into the House, he has to take the permission of the Chair. Mr. Raj Narain had taken permission in the Rajya Sabha. He has not yet taken my permission. Therefore, he must take my permission before bringing the stick here.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : I ask your permission. Kiddly puermit me.

श्रीमती इन्दिरा गांधी की पुलिस ने हमारा पांव चार जगह से तोड़ दिया था । इसीलिए मैं स्टिक लेकर तभी से

चलता हूं । 6 अप्रैल, 1970 को इन्दिरा गांधी की सरकार की पुलिस ने मेरे पांव में चार फ्रेक्चर किये हैं। तभी से यह स्टिक लेकर चलता हूं । यह छड़ी सरकार की है, मेरी नहीं है। छड़ी के बिना मैं चल नहीं सकता हूं।

MR. SPEAKER : Mr Raj Narain has asked for my permission. He has been given permission in the Rajya Sabha. He is physically disabled, he says. I accept his word. Therefore, I permit him to keep the stick.

SHRI K. LAKKAPPA : Can he show the stick at members on this side ? (*Interruptions*).

MR. SPEAKER : Don't record. (*Interruptions*)**

श्री राज नारायण : अगर किसी मेम्बर को यह अहसास हो कि मैंने डंडा दिखाया है तो मैं उस के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, उस के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं । मैंने किसी को डंडा नहीं दिखाया । मैं किसी को डंडा नहीं दिखाता । मैं आप को बताऊं कि मैं ने डा० सम्पूर्णानन्द को चिट्ठी लिखी थी जब उन्होंने यह कहा था कि राज नारायण ने बेंत से पुलिस को मारा । मैंने लिखा था कि मैंने डंडे से नहीं मारा और डंडे से मारने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तो अहिंसा की प्रतिज्ञा ली है । मैं अहिंसक हूं और सत्यवादी हूं । इसलिए मैं किसी को डंडा नहीं दिखा सकता और न डंडे से मार सकता हूं । .... (व्यवधान) ... इसलिए मैंने डंडा नहीं दिखाया है । यह अस्पताल ने हमें दिया है ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I have asked the question; let the Minister reply.

श्री मोहन धारिया : माननीय सदस्य के साथ मैं सहमत हूं कि हमारी एसेंशियल कमोडिटीज के बारे में हमारी एक्सपोर्ट पालिसी कोई एडहाक नहीं रहनी चाहिये, इंटैग्रैटिड होनी चाहिये । इसकी हम कोशिश कर रहे हैं । पिछले साल चाहे शुगर हो या ग्राउंड नट हो कुछ पाबन्दी लगानी पड़ी थी । हम सोच रहे हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज जो हमारे मुल्क की जनता के लिए जरूरी है, उनकी मांग का खयाल कर के ही उनका एक्सपोर्ट किया जाय और हमारी इंटिग्रेटिड पालिसी इस के बारे में हो ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : My question has not been answered. I asked Government to give a relief of 20% in excise to the sugar mills. That relief has neither been transferred to the consumers, nor to the growers.

SHRI MOHAN DHARIA: Government has taken a decision to release 50,000 tonnes of sugar from the STC. We are making an effort. At the one end, it will be auctioned; and at the other, we shall see that it is made available at Rs. 3-90 through the cooperative shops spread throughout the country. We shall see that relief is given to people all over the country.

SHRI D.B. PATIL : The Minister has just now said that it is the policy of the Government to see that provisions are made available at the proper price. It is the duty of the Government to look to the interests of the consumer. To achieve this aim, are the Government prepared to eliminate the middle men *in toto* ?

SHRI MOHAN DHARIA : Government is concerned about the heavy profiteering made by the middle men. The moment we extend our distribution system through the cooperative shops and through other measures, I have no doubt that this high profit of the middle men could be diminished to a great extent.

श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला : मंत्री महोदय ने बताया है कि आलू और प्याज का एक्सपोर्ट बन्द कर दिया गया है मैं जानना चाहता हूं कि क्या ओनियन और पोटैटो ग्रोअर्ज की तरफ से आपके रिप्रिजैंटेशन इसके बारे में आया है ? देहाती अंचलों के अन्दर यह भावना बढ़ती जा रही है कि शहरों के इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करते हुए उन को फेयर प्राइस नहीं

**Not recorded

दी जा रही है । क्या आप बता सकते हैं कि देहाती अंचलों के अन्दर रहने वाले किसानों के इंटरैस्ट्स को सेफगार्ड करने के लिये और उनको न केवल एडीक्वेट प्राइस बल्कि रिम्युनरैटिव प्राइस भी मिले, इसके विषय में आप क्या करने जा रहे हैं । ?

श्री मोहन धारिया : आलू और प्याज पैदा करने वालों की तरफ से हमें रिप्रिजेंटेशन आए हैं। हमने स्टेट गवर्नमैंट्स को ही नहीं नाफेड को भी कहा है कि वे अच्छी तरह से खरीद करें । मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि किसानों को रिम्युनरैटिव प्राइस मिलनी चाहिये ।

SHRI M.S. SANJEEVI RAO : I am sure the hon. Minister is aware that dehydrated onions and potatoes are a very valuable export industry. Is he also aware that in India, we have a number of industries established in the export of these items ? I know Government has made relaxations for this year. Will he indicate what is Government's long term planning, so that the industrialists can plan properly for expanding this very valuable industry, which is not only a labour-intensive, but also a highly value-added industry ?

SHRI BASHIR AHMAD : Salt and mustard oil are not available in certain parts of the country.

MR. SPEAKER : You are going on to salt. But it does not arise from this question. Now the next question.

Visit of Chinese Delegation to India

*533. SHRI PRASANNBHAI MEHTA : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that STC has invited Chinese to visit India and ascertain themselves the possibilities that exist for their importing engineering and other manufactured goods from India;

(b) if so, the reaction of the Chinese Government;

(c) whether any delegation from China has visited India; and

(d) if, so, the outcome of the visit ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) The four Public Sector Organisations which participated in 42nd Canton Trade Fair, of which The State Trading Corporation of India is one, have jointly extended an invitation to five important Chinese Trading Corporations to visit India to see our manufacturing capabilities with a view to expanding trade.

(b) The response of the Chinese side is awaited.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

SHRI PRASANNBHAI MEHTA : I would like to know from the hon. Minister the names of the organisations other than the STC which extended the invitation to the Chinese Trading Corporations and also the names of the Chinese Trading Corporations. Secondly, what were the principal factors which attracted our organisation to invite these trading corporations of China ? Thirdly, when were the formal invitations forwarded to the Chinese Trading Corporations.

श्री आरिफ बेग : श्रीमन्, जो 42वां कैन्टन फ़ेयर था उसमें भाग लेने के लिये हमारे देश की स्टेट ट्रेडिंग कोरपोरेशन, ऐसोसियेशन आफ़ इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज और बैसिक केमिकल्स, फ़ार्मास्यूटिकल और कौस्मेटिक्स और एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, इन सब ने विज़िट किया और वहां पर जिन चाइनीज़ ऐसोसियेशन्स को हमारी इन संस्थाओं की तरफ से निमंत्रण दिया गया उनके नाम इस प्रकार हैं : —

(1) China National Light Industrial Products Import and Export Corporation; (2) China National Metals and Minerals Import and Export Corporation ; (3) China National Machinery Import Export Corporation; (4) China National Chemicals Import and Export Corporation (5) China National Technical Impor Corporation, and (6) China National Cereals, Oils and Foodstuffs Export Promotion Corporation.

इस तरह से इन पांच कौरपोरेशन्स को हम ने इन्विटेशन दिया । हमारा इन्विटेशन गया हुआ है, अभी तक उनकी ओर से हमें जवाब नहीं मिला है।